(ख) वर्ष 1966-97 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अल्मोड़ा, पौड़ी तथा चमोली जिलों में क्रमशः 47, 53 तथा 27 बसे हुए गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया है।

(ग) जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सूचना के अनुसार जिला सलाहकार समिति द्वारा चुने हुए गांवों के आकार पर ध्यान न देते हुए इन्हें विद्युतीकरण के लिए हाथ में लिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Additional Capacity to Meet Energy Requirement

2044. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Working Group on Power has projected 55761 MWs additional capacity to get over the prevailing energy shortages;

(b) whether this additional capacity for power is likely to be the target in the 9th Five Year Plan;

(c) what is the estimated outlay requirement for power sector in that plan;

(d) whether target set for the 8th Five Year Plan has been achieved or is likely to be achieved;

(e) if not, the details in this regard; and

(f) whether the Ninth Five Year Plan for power is being prepared by the Working Group on the basis of the internal resources; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) and (f) The Working Group on Power for 9th Plan has recommended a capacity addition of 57735MW during 9th Plan to meet the power requirements projected by 15th Electric Power Survey Committee.The targets for the Ninth Plan and outlay are still under finalisation by the Planning Commission.

(d) and (e) As against a capacity addition programme of 30537.7 MW during the Eighth Plan, the achievement is expected to be around 17668 MW. The main reasons for shortfall have been paucity of resources with the States, rehabilitation & resettlements issues, law and order etc.

राज्य बिजली बोर्डों के घाटे

2045. **श्री गोपाल सिंह सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 में 31 दिसम्बर, तक गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को, वार्षिक रिपोर्टों और केन्द्रीय सरकार के आंकलन के अनुसार, बिजली के उत्पादन एवं वितरण में तुलनात्मक दृष्टि के लोगों से कितना-कितना घाटा या लाभ हुआ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन में लगातार आई गिरावट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) कुछ रा०बि०बो० के लेखों का निर्धारण न होने की वजह से, वर्ष 1995-96 हेतु सभी रा०बि०बो० की अधिशेष / कमी उपलब्ध नहीं है। तथापि, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड सहित रा०बि०बो० की अधिशेष / कमी ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को गणना में लेकर, जैसा कि वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 हेतु लेखों में प्रदान किया गया है, क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों / विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति तीव्रता से गिर रही है तथा विद्युत क्षेत्र के भावी विकास को व्यवहार्य राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार के बगैर नहीं बनाए रखा जा सकता।